भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1507 का उत्तर

पुंछ और राजौरी जिलों के लिए रेल सेवा

1507. श्री मियां अल्ताफ अहमद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू - कश्मीर के दो सीमावर्ती और पहाड़ी जिले अर्थात् पुंछ और राजौरी बहुत लंबे समय से रेल सेवा से वंचित हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा पुंछ और राजौरी जिलों को रेल सम्पर्क से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दोनों जिलों को रेल सम्पर्क से जोड़ने में लगने वाले समय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

पुंछ और राजौरी जिलों के लिए रेल सेवा के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री मियां अल्ताफ अहमद के अतारांकित प्रश्न सं. 1507 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और निष्पादित की जाती हैं न कि राज्य/जिला/शहर-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के पार फैली हो सकती हैं।

अखनूर और राजौरी के रास्ते जम्मू और पुंछ के बीच नई लाइन (223 किमी) के लिए सर्वेक्षण किया गया था। इस परियोजना की लागत 22771 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

रेल परियोजनाओं की स्वीकृति भारतीय रेल की एक सतत और गतिशिल प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम छोर से संपर्क, मिसिंग लिंक, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी के साथ वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़/संतृप्त लाइनों में वृद्धि, सामाजिक-आर्थिक पहलुओं आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की दायिताओं, निधि की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ने वाले 5 सर्वेक्षण (04 नई लाइन और 01 दोहरीकरण), जिनकी कुल लंबाई 326 किलोमीटर है, को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के तहत विभिन्न आर्थिक जोनों में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना के विकास के लिए शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य एकीकृत योजना बनाना, बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता और यात्रियों, माल और सेवाओं के निर्बाध आवागमन, औद्योगिक समूहों, पत्तनों, खानों, विद्युत संयंत्रों, पर्यटन और सांस्कृतिक स्थानों सहित कृषि क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए कमियों को दूर करना है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य में पड़ने वाली उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला नई रेल लाइन परियोजना जिनकी कुल लंबाई 272 किलोमीटर और लागत 41,000 करोड़ रुपये है, निर्माण के चरण में हैं, जिसमें से 255 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक, इन पर 38,931 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

वर्ष 2014 से, भारतीय रेल पर परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन और तदनुरूपी परियोजनाओं की कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पंजाब राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है -

अवधि	औसत परिव्यय	वर्ष 2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2009-14	1,044 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2023-24	6,003 करोड़ रु.	लगभग 5.75 गुना

*****